

प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों के हित में लिया गया यह निर्णय सराहनीय एवं स्वागत योग्य– अशोक कुमार

संवाददाता

रायबरेली । मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज लोक भवन, लखनऊ से आउटसोर्स कार्मिकों के बड़े हुए पारिश्रमिक की घोषणा के साथ 30प्र0 आउटसोर्स सेवा निगम के लोगों का अनावरण तथा वेबसाइट एवं पोर्टल का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री जी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का जनपद स्तरीय आयोजन सामुदायिक केंद्र, रतापुर में किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों ने कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा तथा मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुना।

सलोन अशोक कुमार, प्रशासक कार्यक्रम का शुभारम्भ विधायक



सलोन अशोक कुमार, प्रशासक जिला पंचायत रंजना चौधरी,

जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, जिलाधिकारी सरनौत कौर ब्रोका एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया

गया। इसके उपरान्त उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने लोक भवन, लखनऊ से प्रसारित मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ वितरण किया गया, जिसमें श्रम विभाग के अन्तर्गत मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना तथा कन्या विवाह सहायता योजना के विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं नग्न पालिका के विभिन्न वाडों के सफाई कर्मचारियों को सफाई किट का वितरण किया गया।

इस अवसर पर विधायक सलोन अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों के हित में लिया गया यह निर्णय सराहनीय एवं स्वागत योग्य है।

धरातल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पारिश्रमिक में वृद्धि सरकार की संवेदनशीलता एवं कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इससे आउटसोर्स कार्मिकों में उत्साह एवं कार्य के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता का संचार होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के हित एवं सम्मान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कार्मिकों को बेहतर आर्थिक संबल मिलने से उनके परिवारों को भी इसका सीधा

अज्ञात चोरों ने गरीब के घर बोला धावा उठा ले गए अनाज

महराजगंज रायबरेली । चन्दापुर थाना क्षेत्र में चोरों ने गरीब को निशाना बनाते हुए पांच बोरी गेहूं जो घर में भूसा में छुपा हुआ था उसे पार कर दिया। चन्दापुर थाना क्षेत्र के पहरावां गांव निवासी देशराज ने लिखित शिकायती पत्र देते हुए थाना चन्दापुर को बताया कि घर पर रखा हुआ गेहूं पांच बोरी अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में उठा ले गए प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है उसके घर पर खाने को गेहूं नहीं है देशराज ने चन्दापुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देखकर न्याय की गुहार लगाई।

कच्ची दीवार के नीचे दबने से बुजुर्ग की मौत

महराजगंज रायबरेली। लगातार हो रही बारिश गरीबों पर आफत बनकर बरस रही है चन्दापुर थाना क्षेत्र के नया पुरवा गांव निवासी रघुनाथ की कच्चे मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। चन्दापुर थाना क्षेत्र के नया पुरवा मजरे चन्दापुर गांव निवासी रघुनाथ अपने घर में कच्ची दीवार के बगल में टीना के नीचे सो रहे थे की रात लगभग 12 1२00 बजे परिजनों के मुताबिक अचानक दीवार भर भया कर नीचे गिर गई ।आनन फानन रघुनाथ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महराजगंज लाया गया जहां डॉक्टरों के इलाज के दौरान रघुनाथ पुत्र ननकऊ उम्र 85 वर्ष की मौत हो गई मौके पर चंदापुर पुलिस तथा महराजगंज तहसील की राजस्व टीम पहुंची है।

हरदोई में बारिश बनी काल,कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत



संवाददाता हरदोई।सडीला कोतवाली क्षेत्र के कुरना टिमरुख गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। घर की बाहरी कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। इसके मलबे में दबकर 60 वर्षीय रामविलास पुत्र सरजू की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया गया कि रामविलास बुधवार सुबह अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे बैठे थे। इसी

दौरान अचानक घर की बाहरी दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। दीवार के मलबे में रामविलास दब गए। हादसा होते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़े और आनन-फानन मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है, जिसके चलते कच्ची दीवारें कमजोर हो गई हैं। इसी के चलते यह हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। रामविलास की पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है।उनके परिवार में दो बेटे राजेंद्र कुमार और गौतम कुमार हैं। बुजुर्ग की मौत से दोनों बेटों समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

हरदोई पुलिस ने युवक को अवैध तमंचा व दो जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार

संवाददाता हरदोई। अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन करने वाले अभियुकों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली शहर पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 01 सितंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त प्रदुमन उर्फ सूरज पुत्र रामशंकर उर्फ बहादुर निवासी ग्राम चांद बेहटा, कोतवाली शहर, जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा ,315 बोर तथा दो अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए।इस संबंध में थाना कोतवाली शहर में आर्मस् एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके विरुद्ध कोतवाली शहर में मु0अ0स0 505/22, धारा 380/411 भादवि तथा मु0अ0स0 803/23, धारा 457/380 भादवि के मुकदमे दर्ज हैं।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उ0फि0 वासु कुमार, उ0फि0 ज्ञानेंद्र सिंह तथा का10 चन्देल शामिल रहे।

हरिद्वार व नरौरा से छोड़ा गया 2.92 लाख क्यूसेक पानी,गर्ग का जलस्तर बढ़ा

हरदोई। जिले में गंगा, रामगंगा और गर्ग नदियों के जलस्तर पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। अधिशासी अभियंता, हरदोई खंड शारदा नहर की ओर से 02 को सुबह मिली जानकारी के अनुसार राजघाट पर गंगा नदी का जलस्तर 125.117 मीटर दर्ज किया गया। यहां खतरे का निशान 125.810 मीटर है। इस तरह राजघाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 69.3 सेंटीमीटर नीचे है।

मिली जानकारी के मुताबिक हरदोई में 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई जबकि हरिद्वार से गंगा नदी में 1,07,911 क्यूसेक तथा नरौरा से गंगा नदी में 83,835 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना है। इसके अलावा उत्तराखंड के नानक सागर डैम से गर्ग नदी में 8,716 क्यूसेक तथा ड्यूनी डैम, पीलीभीत से गर्ग नदी में 3,552 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की रिपोर्ट है। रामगंगा नदी के विभिन्न स्थलों पर जलस्तर 160.190 मीटर, 136.680 मीटर और 136.100 मीटर दर्ज हुआ। गर्ग नदी के साड़ी में केंद्रीय जल आयोग साइट पर जलस्तर 128.420 मीटर दर्ज किया गया।जहां चेतावनी बिंदु 129.150 व डेंजर लेबल 129.650 मीटर पर है।

बरही सीएचसी को मिले चार डॉक्टर, ब्रह्मपुर पीएचसी पर भी बढ़ी चिकित्सकों की तैनाती

गोरखपुर। विकासखंड ब्रह्मपुर क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकीय सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को चार नए डॉक्टर सिद्धांत सर्राफा , ओमकार द्विवेदी, सुष्मा खरवार, शिवानी, मिले हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर पर भी चिकित्सकों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से क्षेत्र के ग्रामीणों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर पर डॉ. ओंकार द्विवेदी और डॉ. सिद्धांत सर्राफ की तैनाती की गई है। इसके साथ ही महिला

चिकित्सक डॉ. शिवानी खरवार भी अपनी सेवाएं देंगी। महिला चिकित्सक की तैनाती से विशेष रूप से महिलाओं और गर्भवती मरीजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के तहत प्रत्येक माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन निर्धारित तिथियों पर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक परामर्श और उपचार की सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर पर उपलब्ध रहेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को जांच और उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।क्षेत्र में लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं

और पर्याप्त चिकित्सकों की मांग उठती रही है। ऐसे में नए डॉक्टरों की तैनाती को ग्रामीणों ने सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से मरीजों को समय से इलाज मिलने के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों का भरोसा भी बढ़ेगा। ग्रामीणों संजय द्विवेदी, विशाल द्विवेदी, प्रमोद चौरसिया, सुमेर गुप्ता, पुजारी यादव, ज्योदीप द्विवेदी, संतोष गुप्ता उर्फ पकौड़ी, रमेश निषाद, ललित निषाद, रामनिवास, बीपी निषाद, विजय दुबे और छोटू शर्मा आदि ने डॉक्टरों की तैनाती का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कहा कि नए चिकित्सकों के आने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिलने

की उम्मीद है।ग्रामीणों का कहना है कि ब्रह्मपुर क्षेत्र की बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है। ऐसे में पर्याप्त डॉक्टरों की उपलब्धता मरीजों के लिए बड़ी राहत है। खासकर महिला चिकित्सक की तैनाती से महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अब अधिक सुविधा और बेहतर परामर्श मिल सकेगा।नए डॉक्टरों की तैनाती से स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की बढ़ती संख्या को संभालने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के इस कदम की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यक सुविधाओं, जांच व्यवस्था और विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार किया

तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत होने के बाद रेखा वर्मा का जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत



(राजीव दिवाकर सिंह) सीतापुर----- भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत की गई पूर्व सांसद रेखा वर्मा का जनपद सीतापुर में प्रथम आगमन हुआ। उनके सीतापुर पहुंचने पर पार्टी नेताओं का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि जन-जन को पार्टी से जोड़ते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए वह दिन-रात कार्य करेंगी।

उन्होंने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरे उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जुटना होगा। उन्होंने वर्ष

2014 से पहले के संघर्ष और उसके बाद पार्टी एवं क्षेत्र की सेवा से जुड़े अपने अनुभवों को विस्तार से साझा किया। साथ ही पार्टी की आगामी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी भी कार्यक्रमताओं एवं जनसामान्य को दी।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ल ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा का अभिनंदन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यकर्ताओं से मेहनत एवं ऊर्जा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव केवल जीत का चुनाव नहीं, बल्कि एक इतिहास रचने का चुनाव

है। तथा भाजपा जिला उपाध्यक्ष जया सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा का फूल माला पहनानकर स्वागत नन्दन अभिनन्दन किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने अटल चौक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पड़ाव स्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र गुप्ता की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अशोक रावत, निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक सिधौली मनीष रावत, विधायक मिश्रिख रामकृष्ण भागव, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी, विधायक महमूदाबाद आशा मौर्य, विधायक बिसवां निर्मल वर्मा, निवर्तमान विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन महरोत्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, महिला वर्मा, विपुल प्रताप सिंह, महेंद्र वर्मा, रीतेश सिंह गौर, नैमिष रतन तिवारी, सुधाकर शुक्ला, पटेल रेखा वर्मा, जया सिंह, विश्राम सागर रावौर, कामेश शुक्ला, नीरज अवस्थी समेत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की अगुवाई में जिले की पुलिस ने प्रदेश स्तर पर लहराया परचम



टीमों ने शिकायतों का सिर्फ कागजी निस्तारण नहीं किया, बल्कि शिकायतकर्ताओं से सीधा संपर्क साधकर उनकी राय ली, जहां जनता ने पुलिस की कार्रवाई पर शत-प्रतिशत संतुष्टि जताई। महिला अपराधों और पारिवारिक विवादों में पुलिस की इस तेज-तर्रार कार्रवाई ने अपराधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं, वहीं आम जनता और महिलाओं के बीच सुरक्षा का अहसास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। न्याय में देरी न होने की इसी नीयत ने सीतापुर पुलिस को पूरे उत्तर प्रदेश के शिखर पर बैठा दिया है।

सक्षिप्त खबरें...

अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई

रायबरेली । आबकारी आयुक्त के निर्देश पर जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 प्रशांत कुमार ने हमराहियों के साथ सदर तहसील के थाना गुरुबक्सगंज अंतर्गत बसगावा, गोझारी एवं शिवहला में कच्ची शराब बनाने के अड्डों एवं संदिग्ध घरों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा मौके पर 400 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। मामले में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।

अग्निशमन सुरक्षा प्रशिक्षण को लेकर अग्निशमन दल ने किया रिव्हर्ल,अग्निसुरक्षा से सम्बंधित जानकारीयां

हरदोई।आग लगने की घटनाओं को रोकने और आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी ढंग से राहत एवं बचाव कार्य करने के उद्देश्य से पुलिस कर्मियों को अग्निशमन सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस महानिदेशक एवं आपात सेवाएं उतर प्रदेश, लखनऊ तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरदोई के आदेश के अनुपालन में 02 सितंबर को थाना पाली एवं थाना पचदेवरा में अग्निशमन सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने थानों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आग से बचाव के महत्वपूर्ण उपयोगों का प्रदर्शन किया। साथ ही आग लगने की स्थिति में तत्काल उठाए जाने वाले कदम, अग्निशमन उपकरणों के सुरक्षित एवं प्रभावी इस्तेमाल तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सावधानी बरतने के बारे में विस्तार से बताया गया।प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को यह भी समझाया गया कि आग लगने की सूचना मिलते ही घबराये बिना आग लगने तकाल सूझबूझ और सावधानी के साथ राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जाए, ताकि जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।इस मौके पर अग्निशमन अधिकारी सवायजपुर चौहान गौतम के नेतृत्व में अग्निशमन टीम मौजूद रही। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया।कुल मिलाकर, पुलिस और अग्निशमन विभाग के इस संयुक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य आपात स्थिति में बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ ही आग से होने वाली घटनाओं में त्वरित कार्रवाई और जनसुरक्षा को और मजबूत करना है।

आम के पेड़ से फांसी लगाकर युवक ने दी जान, पुलिस जांच में जुटी

सवायजपुर,हरदोई। सवायजपुर थाना क्षेत्र के कनकापुर गांव में एक युवक ने खेत में आम के पेड़ से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मोचरी भेज दिया। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान लगभग 28 वर्षीय कुलदीप पुत्र रामहेत निवासी ग्राम कनकापुर, थाना सवायजपुर, जनपद हरदोई के रूप में हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।पुलिस के मुताबिक 02 सितंबर को मृतक के परिजनो ने अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। स्थानीय पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है तथा अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है।सीओ हरपालपुर प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि ंदितांक 01 सितंबर को थाना सवायजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि कुलदीप पुत्र रामहेत निवासी ग्राम कनकापुर थाना सवायजपुर द्वारा खेत में आम के पेड़ से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु मोचरी भेजा गया। 02 सितंबर को मृतक के परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

उक्त घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।:-

48 प्राविधिक सहायकों को मिला नियुक्ति पत्र

अमेठी। उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के तहत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति-पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चयन प्रक्रिया के माध्यम से कृषि विभाग में चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद में श्रेणी-3, वर्ग-2 के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए ईमानदारी, निष्ठा और सेवाभाव से कार्य करने का निर्देशित किया।

जनपद अमेठी के लिए यह अवसर विशेष रहा। जिले के कुल 48 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। उन्होंने सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना करते हुए पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।इस अवसर पर अमेठी के उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार भी मौजूद रही। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी।



यह एक तथ्य है कि जनभागीदारी वाले कई सामाजिक अभियान महज मोदी सरकार के अभियान बनकर रह गए हैं। यह स्थिति तब है, जब देश में कई समस्याएं ऐसी हैं, जिनका समाधान जनता की सामूहिक भागीदारी से ही किया जा सकता है।। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जब यह कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद यह वृद्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और आर्थिक आत्मविश्वास का परिणाम है तो कांग्रेस को यह बिल्कुल रास नहीं आया। उसने अर्थव्यवस्था की तमाम कमजोरियों का उल्लेख करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। ऐसा नहीं है कि आर्थिक मोर्चे पर किसी तरह की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य उन्हें गिनाना नहीं, बल्कि यह सिद्ध करना था कि जीडीपी में वृद्धि किसी तरह की उपलब्धि नहीं है। उसने यह काम पूरी शिद्दत से किया और इसके लिए कई प्रवक्ताओं को मैदान में उतारा। निःसंदेह किसी को यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष सरकार को प्रशंसा करेगा। विपक्ष का काम सरकार को खामियों को इंगित करना और उसकी गलतियों के लिए उसे कठघरे में खड़ा करना है। इससे ही सरकारों पर दबाव बनता है और वे सही तरह काम करने के लिए बाध्य होती हैं, लेकिन पिछले लगभग दो दशकों से असहमति की राजनीति अपनी हदों को पार कर विरोध के लिए विरोध की राजनीति में बदल चुकी है। विरोध के लिए विरोध की राजनीति के चलते आज राजनीतिक माहौल इतना कटुतापूर्ण, छिद्रान्वेषी और नकारात्मक हो गया है कि यदि कोई नेता ऐसा कुछ कह दे कि नियमों का पालन करें और संयम एवं अनुशासन का परिचय दें तो विरोधी दल के नेता इसका भी विरोध करने के लिए आगे आ सकते हैं। इसके लिए उनके पास तरह-तरह के (कु)तर्क भी होंगे। कटु एवं नकारात्मक राजनीतिक विमर्श का असर सामाजिक विमर्श पर भी पड़ रहा है। यह एक तथ्य है कि सोशल मीडिया कहे जाने वाले डिजिटल प्लेटफार्मों पर विचार-विमर्श का स्थान गाली-गलौज ने ले लिया है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दलों के आइटी सेल विरोधी दलों के नेताओं पर प्रायः बिलो द बेल्त यानी अपमानजनक प्रहार करते ही रहते हैं। अब ऐसे प्रहार करने के लिए एआइ का भी सहारा लिया जा रहा है। कई बार इसकी चपेट में महिला नेता भी आ जाती हैं। इसके नतीजे में राजनीतिक और सामाजिक माहौल बुरी तरह दूषित हो रहा है। इस प्रवृत्त के दूर होने की कोई सूरत नहीं दिखती। कटुतापूर्ण राजनीति ने महपुरुषों को भी बांट दिया है। अब राजनीति और समाज के स्तर पर लोग किसी राष्ट्रीय दायित्व या अभियान के प्रति कटिनाई से ही एकमत और एकजुट होते दिखते हैं, जबकि देश की कई समस्याएं ऐसी हैं, जिन्हें लोगों की सामूहिक भागीदारी से ही दूर किया जा सकता है, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी से मुक्ति। आज स्वच्छ भारत जैसे अभियान असरहीन होते दिख रहे हैं तो इसीलिए कि इस अभियान में आम जनता की पहली जैसी भागीदारी नहीं दिखती। जब यह अभियान शुरू हुआ था तो आम लोगों की इसमें दिलचस्पी और भागीदारी दिख रही थी कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैले, लेकिन अब वह दिखाई नहीं देती। यह एक ऐसा अभियान है, जो आम जनता की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। यदि लोग सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से रोकने के लिए सक्रिय-सचेत नहीं रहते तो सरकारें और उनकी एजेंसियां कुछ भी कर लें, बात बनने वाली नहीं है। विडंबना यह है कि जब से यह अभियान शुरू हुआ, तबसे शायद ही किसी विपक्षी नेता ने इसे सफल बनाने में अपने लोगों को भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया हो। कुछ ऐसी ही स्थिति बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की भी है। विरोधी राजनीतिक दलों को लगता है कि जिस दल ने इन अभियानों को शुरू किया, उनके लोगों को ही इनमें भागीदार बनने की आवश्यकता है। शायद यही कारण है कि हर घर तिरंगा जैसे अभियानों में भी सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं दिखती। इसमें गहन संदेह है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विरोधी राजनीतिक दल किसी तरह का उत्साह-उमंग दिखाते होंगे। हैरानी नहीं कि मोदी सरकार के हटते ही इस दिवस को मनाना ही बंद कर दिया जाए। यह एक तथ्य है कि जनभागीदारी वाले कई सामाजिक अभियान महज मोदी सरकार के अभियान बनकर रह गए हैं। यह स्थिति तब है, जब देश में कई समस्याएं ऐसी हैं, जिनका समाधान जनता की सामूहिक भागीदारी से ही किया जा सकता है। संकट यह है कि अब राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे पर एकमत नहीं होते-न तो संसद में और न ही संसद के बाहर। हालांकि इसके लिए राष्ट्रीय एकता परिषद के रूप में एक मंच है, लेकिन वह लंबे समय से निष्क्रिय है। यह सही समय है कि इस निष्क्रिय मंच को सक्रिय किया जाए। राष्ट्रीय एकता परिषद एक गैर-संवैधानिक निकाय है। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, उद्योग, व्यापार, मीडिया और श्रमिक संघों के प्रतिनिधि होते हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कहीं यह मंच इसलिए तो निष्क्रिय नहीं है कि इसकी स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी? जो भी हो, यह ध्यान रहे कि इस परिषद का उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संकीर्णता जैसी समस्याओं का सामना करना था। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता कि इन समस्याओं का सामना करने की आवश्यकता आज भी है और इसकी पूर्ति सबके सहयोग से ही संभव है।

पूर्वोत्तर भारत के ईसाई संगठनों ने कहा एफसीआरए में प्रस्तावित बदलाव दमनकारी

“मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 9 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्र और उसके गृह मंत्री से एफसीआरए संशोधन बिल को वापस लेने और इसे और गहन विचार-विमर्श के लिए जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को भेजने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 6 अगस्त को नई दिल्ली में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ शाह से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया था।

रवीन्द्र नाथ सिन्हा
पूर्वोत्तर भारत के ईसाई संगठन- जहां मिजोरम, नागलैंड और मेघालय जैसे तीन राज्यों में ईसाई आबादी बहुत ज्यादा है- फरिन कंटीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट (एफसीआरए) बिल, 2026 के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालात के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा है। जेपीसी के लिए यह आम बात है कि वह अपनी राय

तय करने से पहले सभी संबंधित पक्षों, जिनमें प्रभावित पक्ष भी शामिल हैं, की बातें सुने। सत्ता पक्ष ने जेपीसी से संसद के मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया था, परन्तु काम की गंभीरता और विषय की संवेदनशीलता के देखते हुए, जेपीसी को अपनी रपट तैयार करने में देर हो रही है। इस बातचीत की प्रक्रिया में पूर्वोत्तर के कई चर्च काउंसिल और उनके मुख्य संगठन शामिल हैं। इनमें %असम क्रिश्चियन फोरम%, %यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट ऑफ नॉर्थ-ईस्ट इंडिया% और %नॉर्थ-ईस्ट इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल% जैसे

विचार विमर्श

कौशल मिलेगा, रोजगार कहां मिलेगा?

“भारत में केवल 8.26प्रतिशत स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार में हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों के दो करोड़ विद्यार्थी शिक्षा और रोजगार के बीच गहरे बेमेल का सामना कर रहे हैं। विद्यार्थी प्रायः सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थिर वेतन, सुरक्षित भविष्य जैसी वजहों से सरकारी नौकरी की पात्रता हेतु डिग्री को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी नौकरी को सम्मानजनक और स्थायी माना जाता है।

अरुण कुमार डजायक
विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीति आयोग ने कौशल विकास को पुर्नव्यवस्थित करने की पहल की है। वित्त बारह वर्षों में 7.67 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास पर गत वर्ष 34,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लेकिन राज्यों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के योगदान के बावजूद परिणाम असमान

प्रह्लाद सबनानी

विकास सिंह
कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में तनावग्रस्त अर्जुन का मानसिक संकट अवेद के संदर्भ में सोचें तो कुछ-कुछ बर्नआउट और एंजायटी से जुड़ा प्रतीत होता है। कृष्ण पहले उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। फिर धैर्यपूर्वक संवाद के जरिये आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल जैसे आजकल के मनोवैज्ञानिक थैरेपी देते हैं। गीता सिखाती है कि तनाव का समाधान परिस्थितियां बदलने में नहीं, सोच बदलने में है।

कुरुक्षेत्र की सुबह। अठारह अश्वहिण्णी सेना आमने-सामने खड़ी है। शंखनाद हो चुका है। ठीक उसी समय महान धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। शरीर शिथिल पड़ गया है। मुंह सूख सा रहा है। वह कहते हैं, ‘मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव’। यह दृश्य आज अगर किसी कॉर्पोरेट दफ्तर में घटे तो हम इसे पैनिक अटैक कहेंगे, बर्नआउट का चरम बिंदु। सोचिए एक सीनियर मैनेजर की, जो सालों की मेहनत के बाद बड़े प्रोजेक्ट की ठीक लॉन्चिंग के एक दिन पहले टीम



बने हुए हैं। अध्ययन ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक एवं अनौपचारिक रोजगार, शिक्षा-रोजगार-प्रशिक्षण से बाहर के युवा और महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 60 करोड़ नागरिकों को अपने दायरे में लिया है। भारत में केवल 8.26प्रतिशत स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार में हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों के दो करोड़ विद्यार्थी शिक्षा और रोजगार के बीच गहरे बेमेल का सामना कर रहे हैं। विद्यार्थी प्रायः सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थिर वेतन, सुरक्षित भविष्य जैसी वजहों से सरकारी नौकरी की पात्रता हेतु डिग्री को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी नौकरी को सम्मानजनक और स्थायी माना जाता है, इसलिए व्यावसायिक तथा ऑनलाइन शिक्षा पर उनका भरोसा अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में सवाल है—नई कौशल व्यवस्था इस बेमेल को दूर करेगी या डिग्रियों के ऊपर कौशल प्रमाणपत्रों की एक और परत जोड़ देगी? अध्ययन के अनुसार मौजूदा व्यवस्था की प्रमुख कमियों में विश्वसनीय करियर मार्गदर्शन का अभाव, स्कूलों में कौशल शिक्षा का सीमित प्रसार, उच्च शिक्षा का उद्योग और अप्रेंटिसशिप से कमजोर जुड़ाव और

अनौपचारिक कामगारों के लिए प्रशिक्षण की लागत और समय जैसी बाधाएं शामिल हैं। काफी हद तक सैद्धांतिक शिक्षण- प्रशिक्षण का कार्यस्थल की जरूरतों से न्याय मेल नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में व्यावसायिक शिक्षा और रोजगारपरक कौशल का प्रावधान है, पर क्रियान्वयन सीमित है। इसलिए स्कूल स्तर से कौशल शिक्षा, उद्योग ही %कौशल ट्रैक’ शुरू हों, जिन्हें स्कूलों की क्षमता और संसाधनों के अनुसार राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाए। उच्च शिक्षा में सामान्य डिग्रियों के बजाय उद्योग आधारित विशेषज्ञता, अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री और %सिखते हुए कमाने’ जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही उद्योग-शिक्षण संस्थानों की भागीदारी, कम अवधि के मांड्यूल तथा लचीली प्रवेश-निकास व्यवस्था विकसित की जाये। नीति आयोग ने कौशल प्रशिक्षण को बदलती रोजगार मांग से जोड़ने पर जोर दिया है—हरित उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन और उभरते क्षेत्रों के लिए नए कौशल तथा घटते क्षेत्रों में

तनाव-मुक्ति के लिए श्रीकृष्ण की मनोवैज्ञानिक थैरेपी



रही है। अर्जुन के लक्षणों की सूची पढ़िए तो किसी मनोचिकित्सक की विलिनकल नोटबुक जैसा लगेगा। शरीर कांपना, रोंगटे खड़े होना, हाथ से धनुष का फिसल जाना, त्वचा में जलन, सिर का चकराना, खड़े रहने में असमर्थता। यह वही सूची है, जो आज एंजायटी डिसऑर्डर के शारीरिक लक्षणों में गिनी जाती है। मगर असली मसला शरीर का नहीं,

अर्थ का है। अर्जुन पूछता है, जिस जीत के लिए मैं लड़ने जा रहा हूं, उसके बाद बचेगा ही क्या? स्वजनों को भाकर मिलने वाला राज्य किस काम का? हमारे उसी मैनेजर से पूछिए कि प्रोजेक्ट लॉन्च की रात वह क्यों टूटा, तो जवाब कुछ ऐसा ही मिलेगा- यह सब पाकर भी आखिर बचेगा क्या, परिवार को दिया वक्त, नींद, सुकून, सब गवाकर। यहां से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है।

प्रसंस्करण या सौर ऊर्जा संयंत्र संचालन-पर जोर देना होगा। केवल शहरी नौकरियों पर ध्यान देने से ग्रामीण युवाओं में निराशा बढ़ेगी। घटती कुल प्रजनन दर के साथ बच्चों की देखभाल का बोझ कम होने से महिलायें वैकल्पिक रोजगार तलाश रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या अभी भी घरेलू काम जैसे कम वेतन और सीमित प्रगति वाले रोजगारों तक सीमित है। इसलिए उन्हें केवल कौशल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि शिक्षा और योग्यता के अनुरूप सुरक्षित, सम्मानजनक और आगे बढ़ने के समान अवसर वाले रोजगार चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में नया क्या है? इसमें उद्योग एग मुद्दे पहले भी विशेषज्ञों की चिंता का विषय रहे हैं। रोजगार सूचना की पहल भारत सरकार ने 1970 के दशक में %रोजगार समाचार% से शुरू की थी। इसके एक दशक बाद, 1984 में जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने भी ऐसा ही प्रकाशन आरंभ किया। इसमें नौकरी के विज्ञापन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शक आलेख प्रकाशित होते थे। असली सवाल है—क्या समस्या केवल कौशल की कमी है? बड़े कौशल-अवसरचना ढांचे के लिए निवेश कहां से आएगा? जब उच्च शिक्षा की डिग्री ही रोजगार से नहीं जुड़ पा रही, तो अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण कितना कारगर होगा? कक्षा 6 से कौशल शिक्षा शुरू करने का सुझाव सवाल उठाता है-पहले से बोलित पाठ्यक्रम में नया भार कितना उचित है? 1960 के दशक में गांधीजी की %नई तालीम% के अनुरूप प्रारम्भ की गई बुनियादी प्राथमिक शालाओं और तकनीकी विद्यालयों के प्रयोग अपेक्षित

कृष्ण, अर्जुन को झिड़कते नहीं, यह भी नहीं कहते कि उठो, कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। वे पहले उसे बोलने देते हैं, पूरी बात कहने देते हैं। पूरा पहला अध्याय असल में एक बलाइंट का पहला काउंसलिंग सेशन है, जिसमें वह बिना रोक-टोक अपनी उलझन उड़ेल देता है। कृष्ण, अर्जुन को कमजोर घोषित नहीं करते, न उसकी भावनाओं को खारिज करते हैं। वे धीरे-धीरे संवाद की दिशा बदलते हैं और उसके बाद के अठारह अध्याय किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि क्रमिक, सोचे-समझे संवाद की तरह आगे बढ़ते हैं। कोई अनुभवी काउंसलर भी यही करता है, एक सेशन में समाधान नहीं थोपता, धीरे-धीरे व्यक्ति को उसकी उलझन की जड़ तक ले जाता है। कृष्ण अर्जुन की समस्या को चुटकी बजाकर गायब नहीं करते, कोई दैवीय शॉर्टकट नहीं देते। कर्म, स्वधर्म, आसक्ति और वैराग्य जैसी अवधारणाओं के जरिए वे उसे यह समझाते हैं कि तनाव अवसर परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति को देखने के अपने नजरिए से जन्म लेता है। ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा

फलेषु कदाचन’ को आज की भाषा में कहें तो यह वही सिद्धांत है, जिसे परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में ‘प्रोसेस-ओरिएटेशन’ कहा जाता है- नतीजे पर नहीं, अपने नियंत्रण में मौजूद कर्म पर ध्यान। सुनने में यह किसी दफ्तर की मीटिंग की सलाह जैसा लगता है, पर इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज के महंगे कॉर्पोरेट कोच इसी बात को नई पैकेजिंग को बेचते हैं। गीता के अंत में अर्जुन उठ खड़ा होता है, यह कहते हुए कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हुई, अब मैं तैयार हूं। यह जीत का ऐलान नहीं, आत्म-स्पष्टता की वापसी है। हर अच्छे थैरेपी सेशन का यही मकसद होता है, व्यक्ति को समस्या से भगाना नहीं बल्कि उसे इतना स्थिर बना देना कि वह खुद अपना रास्ता चुन सके। आज जब बर्नआउट पर खुलकर बात होने लगी है, थैरेपिस्ट के पास जाना अरु शर्म की बात नहीं रही, तब कुरुक्षेत्र का यह दृश्य पर सिर से पड़े जाने लायक है। कृष्ण किसी चमत्कारी उद्घाटकर्ता की तरह नहीं आते बल्कि एक धैर्यवान सुनने वाले की तरह, जो सामने बैठे ईंसान को यह भरोसा दिलाता है

बनघुसरा पंचायत में विकास कार्यों की जांच, अभिलेखों की कमी से उठे सवाल

संवाददाता
विशेश्वरगंज, बहराइच। ग्राम पंचायत बनघुसरा में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर मंगलवार को अधिकारियों की टीम ने जांच की। जांच के दौरान कई कार्यों से संबंधित अभिलेख अधूरे मिलने तथा कुछ कार्यों की फाइलें उपलब्ध न होने की बात सामने आई। इससे जांच की प्रक्रिया और शिकायतों की वास्तविकता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता पवन कुमार पुत्र लल्लन प्रसाद निवासी बनघुसरा ने ग्राम पंचायत में पिछले करीब पांच वर्षों के दौरान नल मरम्मत एवं अन्य संबंधित कार्यों के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक इन कार्यों में करीब 22 से 25 लाख रुपये खर्च किए जाने का दावा है,

लेकिन जांच के समय अधिकारियों को केवल लगभग 25 नलों से संबंधित अभिलेख ही उपलब्ध कराए जा सके। शिकायतकर्ता का कहना है कि उपलब्ध फाइल भी पूरी नहीं थी और उसमें करीब छह से सात लाख रुपये के भुगतान का ही विवरण स्पष्ट रूप से सामने आया। पंचायत भवन के खर्चों का भी मामला जांच के दौरान पंचायत भवन से जुड़े कार्यों के अभिलेखों को भी देखा गया। शिकायतकर्ता के अनुसार फोटोकॉपी, स्टेशनरी, साफ-सफाई और टाइल्स आदि मदों में भुगतान किया गया है। इनमें टाइल्स से संबंधित एक फाइल जांच टीम को मिली, लेकिन वह भी पूर्ण नहीं बताई गई। अन्य मदों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध न होने का आरोप लगाया गया है। गौशाला के भुगतान पर भी मांग



गया हिसाब ग्राम पंचायत की गौशाला में कराए गए विभिन्न कार्यों और मदों में किए गए

भुगतान का रिकॉर्ड भी जांच के दौरान चर्चा में रहा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मांगे जाने के बावजूद कई भुगतानों से संबंधित दस्तावेज जांच टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं ग्राम प्रधान बलदेव से जानकारी लेने पर भी कुछ भुगतान के संबंध में संतोषजनक विवरण नहीं मिल पाने का दावा किया गया है। कायाकल्प समेत कई कार्य जांच के घेरे में ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के तहत कराए गए कार्य, झूम पाइप तथा सोखपिट निर्माण के नाम पर हुए भुगतानों को लेकर भी शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक जांच के समय कायाकल्प से संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण इस कार्य की विस्तृत रिपोर्ट नहीं हो सकी। इसी प्रकार अन्य निर्माण एवं विकास कार्यों के मूल

अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग भी जांच के दौरान सामने आई। अभिलेख नहीं तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल जांच टीम में कृषि विभाग के डीडीएजी, डीआरडीए के सहायक अभियंता, कृषि विभाग के जेई और उद्यान अधिकारी मौजूद रहे। शिकायतकर्ता पवन कुमार का कहना है कि जब शिकायत में शामिल कई कार्यों की मूल फाइलें और भुगतान से संबंधित अभिलेख ही जांच टीम के सामने नहीं हैं तो जांच किस आधार पर पूरी होगी, यह महत्वपूर्ण सवाल है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने ग्राम स्वराज पोर्टल से ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों के बिल और वाउचर पहले ही प्राप्त कर रखे हैं। उनका आरोप है कि पूर्व में भी हुई जांच में सभी मूल अभिलेखों की समुचित पड़ताल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि

वर्तमान जांच की रिपोर्ट आने के बाद यदि उन्हें जांच में कमी दिखाई देती है तो वह न्यायालय की शरण लेने पर विचार करेंगे। सचिव के निलंबन का भी लगाया आरोप शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत सचिव सुशील कुमार के पूर्व में किसी अन्य भ्रष्टाचार संबंधी मामले में निलंबित होने का दावा भी किया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित विभाग की ओर से निलंबन आदेश की जानकारी खबर लिखे जाने तक उपलब्ध नहीं हो सकी। अब जांच अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ग्राम पंचायत बनघुसरा में कराए गए विकास कार्यों और उनके भुगतान से संबंधित अभिलेखों की वास्तविक स्थिति क्या है तथा शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

स्टडी टेबल पाकर नौनिहालों के खिले चेहरे, सुजोली विद्यालय में हुआ वितरण कार्यक्रम

संवाददाता मिर्हीपुरवा (बहराइच)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मंशा के तहत पीएम श्री सर्विलियन विद्यालय सुजोली में छत्र-छात्राओं को स्टडी टेबल वितरित की गई। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों को घर पर पढ़ाई के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई। नोडल शिक्षक श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि शासन की मंशा बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। स्टडी टेबल वितरण से छत्र-छात्राओं को घर पर नियमित रूप से पढ़ाई करने में सुविधा होगी और उनके अध्ययन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान छत्र आस्मिन पुत्री मो. जाविद, मंतसा पुत्री मो. कलौम तथा छाया पुत्री मिथिलेश वर्मा को स्टडी टेबल प्रदान की गई। स्टडी टेबल प्राप्त करते ही बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। इस अवसर पर ग्राम प्रधान राजेश गुप्ता, विद्यालय समिति अध्यक्ष गोबर्धन सिंह चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता क्रांति मिश्र, छोटे लाल गुप्ता, बल्कू गौतम, शिक्षक अरुण मिश्र, अरुण सिंह, विकास सिंह, राम सुमिरन, मान बिहारी सहित विद्यालय परिवार के शिक्षक एवं छत्र उपस्थित रहे।

गोवध निवारण अधिनियम के वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार, चाकू व बोगदा बरामद

संवाददाता
बहराइच, 02 सितंबर। कोतवाली नानपारा पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से दो चाकू और एक बोगदा भी बरामद किया है। दोनों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रवाना किया गया। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी तथा क्षेत्राधिकारी नानपारा चित्रांशू गौतम के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष गुरुसेन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेम में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान 02 सितंबर को मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नहर पटरी, हाड़ा बसेहरी के पास से मुकदमा अपराध संख्या 0292/2026 से संबंधित दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुछताछ में उनकी पहचान जहरुद्दीन पुत्र हाशिम, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम जुमईपुरवा, गिरधरपुर, थाना कोतवाली नानपारा तथा वसीम पुत्र जहरुद्दीन, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम जुमईपुरवा, गिरधरपुर, थाना कोतवाली नानपारा के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध 11 अगस्त 2026 को राम सुहावन पुत्र तीरथ राम निवासी ग्राम जुमईपुरवा की सूचना के आधार पर कोतवाली नानपारा में धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम

के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो अदद चाकू तथा एक अदद बोगदा बरामद हुआ। बरामदगी के संबंध में पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की। इसके बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रवाना कर दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष गुरुसेन सिंह, उपनिरीक्षक सौरभ पाण्डेय, उपनिरीक्षक जितेन्द्र गौड़, हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह, कांस्टेबल पवन यादव तथा कांस्टेबल श्रीकांत यादव शामिल रहे।

चार दिन बाद टूटा बिजली संकट के खिलाफ अनशन, प्रशासन ने दिया समाधान का भरोसा

मांग रखते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों को सुचारु और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सौंपे गए मांगपत्र में विद्युत व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याएं उठाई गई हैं। विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता के बाद समस्याओं के समाधान के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद युवाओं ने अपना आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई। अनशन समाप्त कराने में मोतीपुर थानाध्यक्ष बहा गौड़, एसडीएम और तहसीलदार की भूमिका रही।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं को महिला सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। महिला पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा 102, एंबुलेंस सेवा 108, महिला हेल्पलाइन 181 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के उपयोग की जानकारी दी

टीमों ने प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा पुलिस विभाग की सुरक्षा सेवाओं की जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा उत्पीड़न की स्थिति में वे बिना संकोच संबंधित हेल्पलाइन अथवा पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

आउटसोर्स कार्मिकों को मिला निगम का तोहफा

संवाददाता बहराइच, 02 सितम्बर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित लोकभवन सभागार में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारम्भ किया। इस दौरान निगम के पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग के साथ आउटसोर्स कार्मिकों को चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कपूरथला परिसर स्थित उत्थान आडिटोरियम में किया गया। यहां मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पाण्डेय, नगर पालिका अध्यक्ष सुधा देवी व पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्यामकरन टेकड़ीवाल ने आउटसोर्स कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र व किट प्रदान कर सम्मानित किया। सफाई कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के तहत चार लाभार्थियों को कन्या विवाह सहायता योजना में 85-85 हजार रुपये के डेमो चेक प्रदान किए गए।

गैंगस्टर एक्ट के दोषसिद्ध अभियुक्त को दो वर्ष का सश्रम कारावास

संवाददाता बहराइच, 02 सितंबर। +ऑपरेशन कन्विक्शन+ अभियान के तहत बहराइच पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रानीपुर क्षेत्र में पुलिस को गश्त एवं भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि अशरफ बंजारा के नेतृत्व में एक सक्रिय आपराधिक गिरोह संचालित है। गिरोह के सदस्य संगठित रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से संधेमारी, नकबजनी, ताला तोड़कर चोरी सहित विभिन्न आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। इन गतिविधियों के चलते क्षेत्र में लोगों के बीच भय और आक्रोश का माहौल होने की बात सामने आई थी। इस मामले में थाना रानीपुर में मु0अ0सं0 09/2023 के तहत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) में मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान तथा अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश तथा पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में +ऑपरेशन कन्विक्शन+ के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषियों को अधिकतम एवं त्वरित सजा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, बहराइच श्री सुनील प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त अशरफ बंजारा पुत्र इलाही, निवासी मोहल्ला घोसियाना, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच को दोषसिद्ध करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अपराध में दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। इस दोषसिद्ध में थाना रानीपुर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक (एडीजीसी) श्री सुरेन्द्र सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 मनोज कुमार तथा थाना पैरोकार का0 राम सिंह यादव की प्रभावी पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सक्षिप्त खबरें...

परिवार परामर्श केंद्र ने तीन परिवारों में कराया सुलह-समझौता, टूटने से बचाए रिश्ते

संवाददाता
बहराइच, 02 सितंबर। पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने और पारिवारिक विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराने के लिए पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में केंद्र की टीम ने पारिवारिक विवाद से जुड़े तीन मामलों में दोनों पक्षों को समझाकर सुलह-समझौता कराया और परिवारों को टूटने से बचाया। पुलिस अधीक्षक के समक्ष पारिवारिक विवादों को लेकर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए परिवार परामर्श केंद्र को निर्देशित किया गया था। केंद्र की टीम ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना और विवाद के कारणों को समझने के बाद दूसरे पक्ष से संपर्क कर उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र पर बुलाया। केंद्र पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद टीम ने उन्हें पारिवारिक जीवन के महत्व, आपसी सामंजस्य और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हुए समझाया। काउंसिलिंग के दौरान दोनों पक्षों ने भविष्य में आपस में लड़ाई-झगड़ा न करने तथा पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मिल-जुलकर खुशी से रहने पर सहमति जताई। सुलह होने के बाद परिवार परामर्श केंद्र की टीम ने दोनों पक्षों को एक-दूसरे के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने तथा अपने पारिवारिक दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करने की सलाह दी। पुलिस के इस प्रयास से तीन परिवारों में विवाद समाप्त हुआ और रिश्तों को टूटने से बचाने में सफलता मिली। समझौता कराने वाली टीम में उपनिरीक्षक रमाशंकर मिश्रा, महिला मुख्य आरक्षी संगीता यादव, महिला आरक्षी अनन्या सिंह, गिरजवती यादव, छाया द्विवेदी तथा निश्री त्रिवेदी शामिल रहीं

यातायात पुलिस के सघन चेंकिंग अभियान में 433 वाहनों के चालान, 5.77 लाख रुपये जुर्माना

संवाददाता
बहराइच 02 सितंबर। सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली जनहानि में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध बहराइच पुलिस द्वारा सघन वाहन चेंकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री आयुष विक्रम सिंह तथा क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक यातायात रामप्रकाश एवं यातायात टीम द्वारा 01 सितंबर 2026 को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन चेंकिंग की गई। अभियान के दौरान बस, चार पहिया, तीन पहिया एवं दो पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। यातायात पुलिस एवं नागरिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 433 वाहनों के चालान किए गए तथा 5,77,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। वहीं दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाकर यात्रा करने वाले चालकों के विरुद्ध 34 चालान किए गए, जबकि तेज गति से वाहन चलाने वाले 83 वाहन चालकों के चालान किए गए। अभियान के दौरान हाईवे पर खड़े वाहनों को हटवाते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया और सुरक्षित यातायात के प्रति लोगों को सचेत किया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाएं तथा वाहन को अनियंत्रित गति से न चलाएं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर चेंकिंग एवं कार्रवाई का यह अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा।

रोडवेज बस स्टैंड के पास अवैध स्टैंड बनाकर सवारी भर रहे चार वाहन पकड़े

संवाददाता
बहराइच 02 सितंबर। पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली जनहानि को कम करने के उद्देश्य से यातायात नियमों के उल्लंघन तथा अवैध स्टैंड के विरुद्ध सघन वाहन चेंकिंग अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री आयुष विक्रम सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री रामप्रकाश ने यातायात पुलिस टीम के साथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। अभियान के दौरान बस, चार पहिया, तीन पहिया एवं दो पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। यातायात पुलिस ने विशेष रूप से सड़क किनारे अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा कर सवारियां भरने तथा अवैध स्टैंड बनाकर यातायात व्यवस्था प्रभावित करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी।

पीएम स्वनिधि में बैंकों की सुस्ती पर डीएम सरख्त, एलडीएम को फटकार

- ऋण स्वीकृति में सुधार नहीं हुआ तो बैंकों पर कार्टवाई और क्रियाशीलता बंद करने की चेतावनी, दो ईओ को नोटिस व वेतन रोकने के निर्देश



संवाददाता मऊ। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के शासी निकाय की बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कड़ी नाराजगी जताई। ऋण आवेदनों की स्वीकृति में

लापरवाही मिलने पर उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर जनपद में उनकी क्रियाशीलता बंद करने तक की चेतावनी दी। बैठक में सामने आया

कि जिले के सभी बैंकों में पीएम स्वनिधि के ऋण आवेदनों की औसतन प्रतिदिन महज 10 स्वीकृतियां हो रही हैं। डीएम ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए कहा कि बैंकों की लापरवाही से पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने

डीपीआर से पहले स्थल निरीक्षण अनिवार्य

बैठक में डूडा के परियोजना निदेशक ने बताया कि 233 प्रस्तावों का डीपीआर तैयार कर भेजा जाना है। इनमें स्थलीय जांच के बाद 176 प्रस्ताव डूडा के माध्यम से कराए जाने हैं। डीएम ने सभी प्रस्तावित कार्यों का अनिवार्य स्थल निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। विवादित स्थलों पर आसपास के लोगों से जानकारी लेने और भूमि विवाद की पूरी जांच के बाद ही डीपीआर तैयार करने को कहा।

पीएम आवास योजना में अपात्रों पर नजर

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की समीक्षा में डीएम ने निकाय स्तर पर लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण, शत-प्रतिशत जियो टैगिंग और पात्र लाभार्थियों का सही सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा जिन नगर पंचायतों में एसटीपी के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित एसडीएम से समन्वय कर भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने को कहा गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, संबंधित अधिकारी और लीड

अपर जिलाधिकारी को सबसे कम ऋण वितरण करने वाले बैंकों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने

के निर्देश दिए। समीक्षा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 289 और एसबीआई के 221 आवेदन लंबित पाए गए।

वहीं प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद बड़ौदा यूपी बैंक के 196 और बैंक ऑफ बड़ौदा के 107 आवेदन लंबित मिले। निकाय स्तर पर मऊनाथ भंजन में 2,881 और कोपागंज में 636 आवेदन लक्ष्य के सापेक्ष लंबित पाए गए। पीएम स्वनिधि के तहत निकायों को 19,275 आवेदनों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके मुकाबले अब तक 14,645 ऋण स्वीकृत हुए हैं। अभी 4,630 आवेदन लंबित हैं। डीएम ने कहा कि दूसरे जनपदों में मऊ की तुलना में तीन से चार गुना अधिक ऋण स्वीकृत हो रहे हैं, ऐसे में जिले की खराब प्रगति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को नए आवेदन बढ़ने, लंबित आवेदनों के लाभार्थियों को बैंक तक पहुंचाने और बैंक अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय करने के निर्देश दिए। सबसे कम नए आवेदन और ऋण स्वीकृति करने वाले दो अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उनका वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए।

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, निगाह का शुभारंभ

- भर्ती से वेतन तक पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और पारदर्शी, ईपीएफ इएसआई समेत बीमा व अन्य सुविधाओं का मिलेगा लाभ



संवाददाता मऊ। आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान निगम के पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग, लोगो का अनावरण

सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट वितरित

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के छात्रों ने नुकड़ नाटक प्रस्तुत कर जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट तथा श्रम विभाग के श्रमिकों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अरशद जमाल, मुख्य विकास अधिकारी विवेक श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी, पीडी, सफाई कर्मचारी, आउटसोर्स कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। नगर पालिका परिषद के कम्युनिटी हॉल में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित लोक भवन से आयोजित और आउटसोर्स कर्मचारियों को चेक वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। चयन योग्यता और मेरिट के आधार पर

वेतन से नहीं कटेगा सर्विस चार्ज

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में जाएगा। ईपीएफ और इएसआई का अंशदान नियमित रूप से जमा किया जाएगा और ईपीएफ की राशि कर्मचारी के नाम पर सुरक्षित रहेगी। आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर्मचारी के वेतन से अनावश्यक कटौती नहीं कर सकेंगी। एजेंसी को सरकार की ओर से अलग से सेवा शुल्क दिया जाएगा। इएसआई के माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर कैंशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसे आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मातृत्व अवकाश समेत अन्य वैधानिक सुविधाएं भी कर्मचारियों को मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी आउटसोर्स कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति नहीं होगी। कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर पहले मामले की जांच होगी। गलत शिकायत पाए जाने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दुर्घटना पर 50 लाख तक का बीमा कवर

स्टेट बैंक के साथ हुए एमओयू के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दुर्घटना की स्थिति में वेतन के आधार पर 20 से 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अग्निकांड में 10 लाख रुपये तक, आकस्मिक चिकित्सा के लिए पांच लाख और एयर एंबुलेंस की आवश्यकता होने पर 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार बोझ नहीं, बल्कि प्रदेश के मानव संसाधन के रूप में देखती है। तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में काम करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन मानव श्रम का सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहेगा।

किया जाएगा तथा प्रदेश की आरक्षण नीति का पालन होगा। भर्ती से लेकर पोस्टिंग, उपस्थिति, वेतन, ग्रेज्युटी, बीमा और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन एवं निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एक

ही प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विस डिटेल, बैंक खाता, उपस्थिति, वेतन और वेतन से होने वाली कटौती की जानकारी देख सकेगे। किसी समस्या की स्थिति में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर उसका स्टेटस भी देखा जा सकेगा।

कोटेदारों का लाभांश बढ़कर हुआ 125 रुपये प्रति कुंतल, संघ ने बताया सीएम का आभार



- 35 रुपये की वृद्धि पर उचित दर विक्रेताओं में खुशी, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री व खाद्य मंत्री को सौंपा धन्यवाद ज्ञापन

संवाददाता मऊ। उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के लाभांश में शासन

द्वारा 35 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि किए जाने पर जिले के कोटेदारों में खुशी की लहर है।

लाभांश 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किए जाने के निर्णय को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने कोटेदारों के आर्थिक हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय के प्रति आभार जताया।

पांच साल की अनुरक्षण अवधि में ही उखड़ने लगी सड़क की परत, तीन जगह गहरे गड्ढे

संवाददाता अमिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी बोझी-कटिहारी सड़क की गुणवत्ता पर अनुरक्षण अवधि पूरी होने से पहले ही सवाल उठने लगे हैं। बड़रांव ब्लॉक के पिछले गेट के पास सड़क पर तीन स्थानों पर गहरे गड्ढे उभरने लगे हैं। सड़क की ऊपरी परत भी कई जगह से उखड़ने लगी है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों में हादसे की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई है। सड़क के किनारे लगे शिलापट के अनुसार, मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कराया गया है। इसकी लंबाई 7.100 किलोमीटर है और निर्माण पर करीब 58.48 लाख रुपये की लागत दर्शाई गई है। शिलापट पर सड़क के लिए पांच वर्ष की सामान्य अनुरक्षण अवधि भी अंकित है, जो वर्ष 2029 तक बताई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अनुरक्षण अवधि अभी समाप्त भी नहीं हुई और सड़क पर गड्ढे बनने लगे हैं। बड़रांव ब्लॉक के पिछले गेट के पास तीन स्थानों पर बने गड्ढे लगातार बढ़ने की स्थिति में हैं। बारिश होने और भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने पर इनके और गहरे होने की आशंका है। यदि समय रहते इनकी मरम्मत नहीं कराई गई तो सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो सकता है। गुणवत्ता की जांच की उठी मांग

स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पांच वर्ष की अनुरक्षण अवधि वाली सड़क पर इतने कम समय में गड्ढे उभरना गंभीर मामला है। विभाग को मौके पर जांच करकर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। और क्षतिग्रस्त हिस्से की मानक के अनुरूप तत्काल मरम्मत करानी चाहिए। लोगों ने यह भी मांग की कि संबंधित विभागीय अधिकारी मौके का निरीक्षण कर सड़क की वर्तमान स्थिति का जायजा लें, ताकि शुरुआती स्तर पर ही समस्या का समाधान किया जा सके।

सक्षिप्त खबरें...

रामपुर में 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप, युवक पर मुकदमा

संवाददाता मधुबन। रामपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अशरफ उर्फ साधू पुत्र नसरुद्दीन, निवासी भेड़वरा बारी, थाना रामपुर, जनपद मऊ के खिलाफ धारा 87, 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिलेख के अनुसार घटना 30 अगस्त 2026 को सुबह करीब 3 बजे की है। मामले में 1 सितंबर 2026 की रात 10ः51 बजे मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। किशोरी की तलाश और बरामदगी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर तलाश एवं दबिश दे रही है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक श्याम जी यादव कर रहे हैं।

जिला चिकित्सालय आवास की बिजली कटने से कर्मचारियों में आक्रोश, सामूहिक अवकाश की चेतावनी

संवाददाता मऊ। जिला चिकित्सालय परिसर स्थित कर्मचारी आवासों की बिजली 31 अगस्त से कटे होने के कारण कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को पत्र देकर विद्युत कनेक्शन तत्काल बहाल कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड के निर्देश पर आवासीय कॉलोनी की बिजली काटी गई है। बिजली न रहने से कर्मचारी रात में सो नहीं पा रहे हैं और दिन में ड्यूटी करने में भी दिक्कत हो रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि बकाया बिजली बिल के नाम पर उनके वेतन से कटौती भी की जा चुकी है, इसके बावजूद कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल बिजली बहाल नहीं की गई तो वे मजबूर होकर सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए जिला चिकित्सालय प्रशासन और विद्युत विभाग को जिम्मेदार माना जाएगा।

कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड से वार्ता कर आवासीय कॉलोनी की बिजली शीघ्र बहाल कराने की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

दुकान साफ करते समय सांप के काटने से अधेड़ की मौत

संवाददाता वलीदपुर। मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के इटोरा चौबेपुर गांव निवास एक अधेड़ की मंगलवार को देर शाम दुकान की सफाई करते समय सांप के काटने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के इटोरा चौबेपुर गांव निवास रमेश यादव उम्र 55 वर्ष जिनकी किराने की दुकान कटकटी मोड़ पर है मंगलवार को सां को अपनी दुकान की साफ-सफाई कर रहे थे। इसी दौरान दुकान में छिपे सांप ने उनको काट लिया। सांप के काटने की घटना को अनदेखा करते हुए रमेश दुकान में बैठ गए कुछ देर के बाद जब जहर का असर हुआ तो दुकान में ही बेहोश हो गए परिजनों इसकी जानकारी होने पर आनन-फानन में उनको मऊ फातिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया मौत की सूचना से गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।

ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक मशीनों से जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए

संवाददाता रतनपुरा। समाजवादी जन चिंतक निसार अहमद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी जिला चिकित्सालयों की तरह आधुनिक जांच सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों में सरकार द्वारा अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे, पैथोलॉजी तथा अन्य आधुनिक जांच मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, उसी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। खासकर महिला चिकित्सालयों और प्रसूति सेवाओं वाले केंद्रों में अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे और पैथोलॉजी जांच की सुविधा प्रार्थमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। निसार अहमद ने कहा कि ग्रामीण गरीब मरीज को छोटी-सी जांच के लिए जिला मुख्यालय या निजी जांच केंद्र तक भेजना उसके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता है। आने-जाने का खर्च, काम का नुकसान और निजी जांच की महंगी फीस उसकी परेशानी बढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि सरकार की सदाशयता का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा, जब आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं जिला चिकित्सालयों तक सीमित न रहकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक भी पहुंचें। केवल मशीनें उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ और नियमित संचालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गरीब की मजबूरी को निजी जांच केंद्रों की कमाई का जरिया बनने से रोकने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक जांच सुविधाओं से मजबूत करना समय की आवश्यकता है।

स्वामी, एवं प्रकाशक देवेन श्याम द्वारा राम प्रिंटिंग प्रेस, न्यू यादव बाजार इटौली काकोरी, लखनऊ से मुद्रित करवाकर कार्यालय एच०आई०जी०-ए10/2, टिकैत राय, एल०डी०ए कालोनी, राजाजीपुरम् लखनऊ-17 से प्रकाशित । सम्पादक : अवंतिका देवेन श्याम मो०n०-9580629657 Email-yugsrishti02gmail.com, https://yugsrishti.com/info@yugsrishti.com , पी.आर.बी. एक्ट के तहत इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारो के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय मान्य ।



इस किताब को पढ़कर बदला राशि खन्ना का नजरिया, बोली- ये किताब थेरेपी जैसी लगी

अभिनेत्री राशि खन्ना धीरे धीरे अब हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाकर रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने हाल ही में %द मिडनाइट लाइब्रेरी% पढ़ी, जिसने उनके नजरिए को बदलकर रख दिया है। अभिनेत्री राशि खन्ना ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे %द मिडनाइट लाइब्रेरी% पढ़ती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री का कहना है कि इस किताब ने उनके जीवन में थेरेपी की तरह काम किया है। तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, +%द मिडनाइट लाइब्रेरी- मैट हेग की किताब%। ये किताब मुझे एक थेरेपी की तरह लगी, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इसकी जरूरत है।+



अभिनेत्री ने बताया कि इस किताब ने उनके जीवन को उन पहलुओं पर सोचने पर मजबूर किया है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने लिखा, +इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि हम कितनी आसानी से उन जिंदगियों को अच्छा समझ लेते हैं जो हम जी सकते थे और उन फैसलों पर पछताते हैं जो हमने नहीं लिए, बिना ये जाने कि क्या वो जिंदगियां सच में बेहतर होतीं।

अभिनेत्री ने आखिरी में लिखा, +हमें सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है और हम इसे अपने फैसलों से बनाते रहते हैं और शायद जिंदगी का मतलब ये सोचना नहीं है कि हम कौन बन सकते थे, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह से जीना है जो हम बन रहे हैं।+

%द मिडनाइट लाइब्रेरी%, ब्रिटिश लेखक मैट हेग का एक अत्यंत लोकप्रिय और विश्व स्तर पर प्रशंसित उपन्यास है, जो अगस्त 2020 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक जीवन के अर्थ, पछतावे और उम्मीद पर आधारित है। इस पुस्तक को वर्ष 2020 का गुडरीड्स च्वाइस अवॉर्ड (फिक्शन) मिला था। अभिनेत्री राशि खन्ना की बात करें, वह हाल ही में वेब सीरीज %लुक्खे% में नजर आई थी। राशि खन्ना ने इस सीरीज में %इंस्पेक्टर गुरबानी कौर% का दमदार पुलिसवाला किरदार निभाया है। राशि के अलावा, इसमें लक्ष्यवीर सिंह सरन, पलक तिवारी और मशहूर रैपर किंग (अरिंदम चक्रवर्ती/अर्पण कुमार चंदेल) भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

यह सीरीज चंडीगढ़ की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो ड्रग्स, अंडरग्राउंड पंजाबी हिप-हॉप इंडस्ट्री और संगठित अपराध के इर्द-गिर्द घूमती है।

पद्मावत के जौहर सीन से लेकर हिजाब विवाद तक, जब-जब अपने बयानों से विवादों में घिरीं स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जो अपने एक्टिंग से ज्यादा बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी अभिनेत्री एक विवाद में घिरी हुई हैं। फिल्म %पद्मावत% के जौहर सीन पर दिए गए उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रेल किया जा रहा है। यूजर्स से लेकर कई वर्गों तक से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, यह कोई पहला मौका नहीं है जब अभिनेत्री अपने बयानों को लेकर विवादों में आई हैं, इससे पहले भी कई मौकों पर उनके बयानों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है। आइए देखते हैं किन-किन मौकों पर ऐसा हुआ है। फिल्म %पद्मावत% में जौहर सीन = 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई महिला, जीवन स्वतंत्रता कार्यक्रम के दौरान स्वरा भास्कर ने पद्मावत के जौहर सीन पर बात करते हुए कहा कि इस सीन से रेप सर्वाइवर्स के लिए गलत मैसेज जा सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर वह एक रेप सर्वाइवर होती, तो फिल्म का क्लाइमैक्स देखकर मुझे डरपोक जैसा महसूस होता कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड नहीं किया। क्या हम अपने सर्वाइवर्स को यही बताना चाहते हैं कि वे जीने के लायक नहीं हैं। एक इज्जतदार औरत खुद को मार लेती है, क्या हम यह बताना चाहते हैं कि रेप एक औरत की जिंदगी का अंत है? यह सीन बहुत प्रॉब्लम वाला था। वीडियो के वायरल होने के बाद स्वरा भास्कर ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है। उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि जौहर करने वाली महिलाएं कायर थीं। द्रौपदी का कथन = जनवरी 2022 में उडुपी के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। फरवरी 2022 में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कर्नाटक के हिजाब विवाद और उस पर देश के राजनेताओं व प्रशासन की चुप्पी की तुलना महाभारत की सभा से की थी। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि महाभारत में द्रौपदी के जबर्न कपड़े उतारे गए थे और सभा में बैठे जिम्मेदार, शक्तिशाली, कानून बनाने वाले देखते रहे। ऐसे ही आज याद आया।

%द कश्मीर फाइल्स% = नवंबर 2022 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान इजरायली फिल्ममेकर नादव लैपिड ने इस फिल्म को %प्रोपेगेंडा% कहा था। स्वरा भास्कर ने उनके इस बयान का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, +जाहिर तौर पर यह दुनिया के लिए काफी स्पष्ट है।+

उन्होंने बिना नाम लिए एक पोस्ट में लिखा था कि अगर आप अपनी सफलता की बधाई चाहते हैं, तो पिछले पांच साल लोगों के खिलाफ एजेंडा चलाने में नहीं बिताने चाहिए थे। भारतीय सेना पर ट्वीट = साल 2018 में भारतीय सेना पर स्वरा भास्कर के एक ट्वीट ने काफी हंगामा मचा दिया था। अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए



गुणवत्तापूर्ण नींद है नींव सेहतमंद तन और मन की

स्वस्थ रहने के लिए गुणवत्तापूर्ण नींद जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार, नींद स्वस्थ जीवन की नींव है। पर्याप्त और नियमित नींद शरीर को बेहतर पोषण, ताकत तथा मानसिक संतुलन प्रदान करती है।



स्वस्थ रहने के लिए गुणवत्तापूर्ण नींद जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार, नींद स्वस्थ जीवन की नींव है। पर्याप्त और नियमित नींद शरीर को बेहतर पोषण, ताकत तथा मानसिक संतुलन प्रदान करती है। वहीं नींद की कमी या अधिकता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देर रात जागना, अनियमित दिनचर्या और मोबाइल, लैपटॉप पर इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग नींद को प्रभावित करते हैं। मन की शांति, नियमित दिनचर्या और संतुलित जीवनशैली से अच्छी नींद संभव है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद उन आवश्यकताओं में समाहित हो गई है, जिसकी सबसे अधिक उपेक्षा की जा रही है। देर रात तक मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, काम का तनाव, देर से भोजन, अनियमित दिनचर्या और सुबह जल्दी उठने की मजबूरी ने हमारी प्राकृतिक नींद को प्रभावित किया है। इसका परिणाम केवल सुबह उठने पर थकान के रूप में नहीं मिलता, बल्कि धीरे-धीरे शरीर और मन दोनों की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है। आयुर्वेद ने निद्रा को केवल शरीर को आराम देने वाली अवस्था नहीं माना, अपितु उसे सुख, स्वास्थ्य, पोषण, शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमता और जीवन से जोड़ा है।

आयुर्वेद के अनुसार उचित नींद से शरीर को पोषण मिलता है, शक्ति बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है और कार्य करने की क्षमता बेहतर होती है। इसके विपरीत नींद की कमी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। इसलिए नींद को समय की बर्बादी या आलस्य समझना उचित नहीं है। जिस प्रकार भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार उचित नींद भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। केवल अधिक सोना स्वास्थ्य का संकेत नहीं है। सही समय पर और आवश्यकता के अनुरूप सोना अधिक महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद असमय सोने, आवश्यकता से अधिक सोने और आवश्यकता के बावजूद पर्याप्त नींद न लेने- तीनों को स्वास्थ्य के लिए अनुचित मानता है। स्वस्थ जीवन के लिए सोने और जागने का समय यथासंभव नियमित होना चाहिए। रात्रि का समय शरीर और मन के विश्राम के लिए स्वाभाविक रूप से निर्धारित है। लगातार रात में जागने से शरीर में रूक्षता और वात संबंधी विकार बढ़ने की संभावना रहती है। शरीर में टूटन, थकान, बेचैनी,, सिर भारी रहना, एकाग्रता में कमी और पाचन संबंधी समस्याएं इससे जुड़ सकती हैं। आज की डिजिटल संस्कृति ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। शरीर सोना चाहता है, लेकिन मस्तिष्क लगातार उत्तेजित रहता है। परिणामस्वरूप नींद की अवधि और उसकी गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं। दिन में सोने को भी पूरी तरह निषिद्ध नहीं माना गया है। विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में दिन में थोड़ी नींद लाभकारी हो सकती है। गर्मी के मौसम में शरीर में रूक्षता बढ़ती है और रात अपेक्षाकृत छोटी होती है।

एंटीक ज्वैलरी देगी हरेक ड्रेस को रॉयल लुक



एंटीक गोल्ड नेकलेस आपके पूरे लुक को रॉयल टच दे सकता है। अगर साड़ी हैवी है तो मीडियम साइज का नेकलेस चुनें और अगर साड़ी सिंपल है तो थोड़ा हैवी नेकपीस ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ छोटे झुमके या स्टड ईयररिंग्स पहनें,

एंटीक ज्वैलरी का फैशन सदाबहार है। इसकी खूबसूरती और रॉयल अंदाज हर आउटफिट को खास बना देता है। विंटेज डिजाइन, गोल्डन फिनिश, कुंदन, मोती और ट्रेडिशनल मोटिफ्स इसे बाकी एक्सेसरीज से अलग बनाते हैं। महिलाएं इसे साड़ी-लहंगे के साथ ही... एंटीक ज्वैलरी का फैशन सदाबहार है। इसकी खूबसूरती और रॉयल अंदाज हर आउटफिट को खास बना देता है। विंटेज डिजाइन, गोल्डन फिनिश, कुंदन, मोती और ट्रेडिशनल मोटिफ्स इसे बाकी एक्सेसरीज से अलग बनाते हैं। महिलाएं इसे साड़ी-लहंगे के साथ ही नहीं, कुर्ती, सूट और वेस्टर्न ड्रेस संग भी स्टाइल कर रही हैं। जब आप कोई ड्रेस पहनती हैं तो आपको उसके अनुसार ज्वैलरी को भी कैरी करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपका लुक प्रॉपर नजर नहीं आएगा। जानिये एंटीक ज्वैलरी के बारे में कि किस तरह से आप इस ज्वैलरी को कैरी करके अपने आउटफिट को शानदार लुक दे सकती हैं। यदि देखा जाए तो एंटीक ज्वैलरी का फैशन आउट नहीं होता है। साथ ही इसकी खूबसूरती और रॉयल अंदाज हर आउटफिट को खास बना देता है। एंटीक ज्वैलरी की विंटेज डिजाइन, गोल्डन फिनिश, कुंदन, मोती और ट्रेडिशनल मोटिफ्स इसे बाकी एक्सेसरीज से अलग बनाते हैं। यही वजह है कि आजकल महिलाएं इसे सिर्फ साड़ी या लहंगे के साथ ही नहीं, बल्कि कुर्ती, सूट और यहां तक कि वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी स्टाइल कर रही हैं। यदि आपको अपनी साड़ी को एक खास लुक देना है तो एंटीक नेकलेस कैरी करें। इसका लुक आपको एलिगेंट अंदाज देगा। सिल्क, बनारसी, कॉटन या ऑर्गेजा साड़ी के साथ

अक्षरा सिंह ने आम्रपाली दुबे के बयान पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- किसी की निजी गरिमा का हिसाब देने नहीं बैठी हूं



भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक बार फिर आम्रपाली दुबे के साथ अपने पुराने रिश्ते और पवन सिंह से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा में हैं। आम्रपाली दुबे ने हाल ही में शो %भोजपुरी बवाल% में दावा किया था कि जब अक्षरा के मुश्किल दौर में इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा उनसे दूरी बना रहा था, तब उन्होंने खुलकर उनका साथ दिया था। आम्रपाली ने कहा कि अगर अक्षरा के साथ खड़े होने की वजह से पवन सिंह उनसे नाराज होते या उनके साथ काम नहीं करना चाहते, तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अब अक्षरा सिंह ने आम्रपाली के इन बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह किसी की मदद या अपने रिश्तों का हिसाब लेकर मीडिया के सामने नहीं बैठना चाहतीं। यह बहुत पुरानी बात है और अब इसे बार-बार सामने लाने की जरूरत नहीं है। अक्षरा ने कहा, %%मैं इस बारे में कोई लिस्ट लेकर नहीं बैठी हूं कि मीडिया में आकर यह बताऊं कि मैंने क्या किया, किसने क्या किया या उसने क्या किया। हर इंसान की गरिमा होती

है और मुझे लगता है कि हमें इसे मनोरंजन का साधन नहीं बनाना चाहिए। मैं इस बारे में बार-बार क्या ही बोलूं, यह तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मुझे इन सब बातों पर हंसी आती है। अब यह बात नहीं निकलनी चाहिए। इस बात को जमाना हो गया है।%% अक्षरा ने खास तौर पर आम्रपाली के उस बयान पर भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्षरा ने बाहर आकर यह कहा कि इंडस्ट्री में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि वह मुश्किल समय में उनके साथ थीं। अक्षरा ने कहा, %%आम्रपाली को मेरी किसी बात से तकलीफ हुई थी, तो उन्हें सीधे फोन करके पूछना चाहिए था। अगर किसी बात को

लेकर गलतफहमी थी, तो दाना के बांच बातचात से उसे साफ किया जा सकता था। अब वह किसी एक बात को लेकर रो रही हैं। मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि वे वास्तव में किस बात को लेकर रो रही हैं। मुझे अभी तक यह भी समझ में नहीं आया है कि आखिर क्या बात हुई है?%% इस पूरे मामले की शुरुआत आम्रपाली दुबे के %भोजपुरी बवाल% में दिए बयान से हुई। शो में होस्ट शुभंकर मिश्रा ने उनसे सवाल किया था कि उन पर आरोप है कि उन्होंने अक्षरा को छोटी बहन माना, उनके साथ तस्वीरें शेयर कीं, लेकिन जब अक्षरा मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, तब वह उनके साथ खड़ी नहीं हुई। इसके जवाब में आम्रपाली ने कहा था कि उन्होंने उस समय अक्षरा का साथ दिया था, जब इंडस्ट्री में यह चर्चा थी कि अक्षरा के साथ नजर आने पर पवन सिंह उनके साथ काम करना बंद कर देंगे। इसके बावजूद उन्होंने अक्षरा के साथ खड़ा होना चुना।

उस दौर में जब लोग अक्षरा के साथ तस्वीरें त क

